भारत सरकार

पंचायती राज मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या †450

दिनांक 05.12.2023 को उत्तरार्थ

पंचायत-स्तरीय सूचकांक

†450. श्री रितेश पाण्डेयः

क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का सतत् विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के स्थानीयकरण की कार्यसूची को प्राप्त करने और पंचायतों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए पंचायत स्तरीय सूचकांक जारी करने और पंचायत स्तरीय पुरस्कारों को संस्थागत बनाने का प्रस्ताव है;

(ख) सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण में पंचायतों के कार्य-निष्पादन के मूल्यांकन के मानदण्ड क्या हैं और पहचान किए गए संकेतक, यदि कोई हों, क्या हैं;

(ग) पंचायतों के बीच ज्ञान का आदान-प्रदान सुनिश्चित करने और सफल मॉडलों की प्रतिकृति सुनिश्चित करने के लिए किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या कम कार्य-निष्पादन करने वाली पंचायतों के परिणामों में सुधार सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

पंचायती राज राज्य मंत्री

(श्री कपिल मोरेश्वर पाटील)

(क) जी, हाँ| मंत्रालय 9 विषयों को अपनाते हुए, वर्ष 2030 तक सतत विकास के एजेंडे को प्राप्त करने के लिए सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण की प्रक्रिया का समन्वयन कर रहा है। स्थानीयकृत एसडीजी को प्राप्त करने और इस प्रकार एसडीजी 2030 प्राप्त करने में जमीनी स्तर के संस्थानों द्वारा की गई प्रगति का मूल्यांकन और मापन के लिए, मंत्रालय ने पंचायत विकास सूचकांक पर एक रिपोर्ट जारी की है। पंचायत विकास सूचकांक (पीडीआई) ग्रामीण क्षेत्र में एलएसडीजी प्राप्त करने में कार्य-निष्पादन के मूल्यांकन और प्रगति आंकलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

संशोधित आरजीएसए के तहत, मंत्रालय पंचायतों के बीच सकारात्मक/ स्वस्थ प्रतिस्पर्धा सृजित करने के लिए एसडीजी की प्राप्ति में उनके कार्य-निष्पादन का मूल्यांकन करके राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार (एनपीए) के माध्यम से सर्वश्रेष्ठ कार्य-निष्पादन करने वाली पंचायतों को प्रोत्साहित कर रहा है। पीडीआई की तैयारी में अपनाए गए स्थानीयकृत सतत विकास लक्ष्यों के नौ विषयों पर विषयगत आँकड़े और ग्राम पंचायतों के समग्र पीडीआई आँकड़े से स्थानीयकृत एसडीजी प्राप्त करने में उनकी प्रगति का मूल्यांकन करने में मदद मिलेगी। पीडीआई नौ विषयों के साथ-साथ समग्र पीडीआई आँकड़ों में विकास लक्ष्यों की प्रगति में पंचायतों की तुलना करने में भी मदद करेगा। अत: पीडीआई विकासात्मक लक्ष्यों के लिए योजना बनाने और काम करने के लिए पंचायत के बीच प्रतिस्पर्धी भावना को बढ़ावा देगा और अपने समकक्ष पंचायतों की तुलना में अपनी स्थिति में सुधार करके सभी स्तरों पर समग्र विकास की दृश्यता को बढ़ाएगा।

(ख) पीडीआई रिपोर्ट ने 9 विषयों के स्थानीय संकेतकों, इसके डेटा स्रोतों और निगरानी तंत्रों के आधार पर पंचायत विकास सूचकांक की गणना के लिए गणन पद्धति का उल्लेख किया है। पीडीआई की गणना एलएसडीजी की प्रगति की निगरानी के लिए 9 विषयों, 144 स्थानीय लक्ष्यों और 642 यूनिक डेटा बिंदुओं पर विकास का मूल्यांकन करने वाले 577 स्थानीय संकेतकों पर की जाएगी।

(ग) मंत्रालय ने पीडीआई पर विभिन्न हितधारकों और भागीदारों के साथ ज्ञान का आदान प्रदान करने के लिए विभिन्न दृष्टिकोण अपनाए हैं। विभिन्न हितधारकों के साथ राज्य स्तरीय कार्यशाला/बैठकों की श्रृंखला; पीडीआई को लागू करने के महत्व और संस्थागत कार्यनीतियों संबंधी ज्ञान को बढ़ाने के लिए दृश्य-श्रव्य (एवी) फिल्में, लर्निंग मॉड्यूल आदि को तैयार करना शुरू किया गया है।

पीडीआई पंचायतों को अभिसरण तंत्र के माध्यम से एलएसडीजी के विषयों के विभिन्न नवीन/ नवोन्मेषी मॉडलों पर अनुकरणीय पद्धतियां तैयार करने के लिए भी प्रेरित करेगा। पंचायतों की सर्व श्रेष्ठ प्रथाओं को अन्य राज्यों और पीआरआई के साथ साझा करने की जागरूक प्रक्रिया के माध्यम से पंचायतों की श्रेष्ठ पद्धतियों को अन्य पंचायतों में दोहराया जा रहा है और इसके परिणामस्वरूप अनुभवों और विशेषज्ञता को साझा करने के माध्यम से जमीनी स्तर पर प्रभावी पद्धतियों को अपनाया जा रहा है। राज्यों के भीतर और बाहर पीआरआई का बाहरी दौरा ज्ञान साझा करने का एक अन्य तरीका है। साथ ही, अन्य हितधारकों के बीच पंचायतों द्वारा अपनाई गई श्रेष्ठ पद्धतियों का प्रसार करने के लिए राज्यों में पंचायत शिक्षण केंद्र (पीएलसी) स्थापित किए जा रहे हैं।

(घ) मंत्रालय ने विभिन्न कार्यनीतियों और तंत्रों के माध्यम से पीडीआई को संस्थागत बनाने की प्रक्रिया शुरू की है। राज्यों को मंत्रालय द्वारा अपनाई गई कार्यनीतियों से अवगत कराया जाता है और वे पंचायत स्तर पर परिणामोन्मुख विकास लक्ष्यों के लिए पीडीआई का उपयोग करने हेतु तैयार हैं। पीडीआई का परिणाम एलएसडीजी की उपलब्धि के लिए पंचायत द्वारा प्राप्त अंकों के माध्यम से वृद्धिशील प्रगति को मापेगा और पीडीआई का आधारभूत डेटा कार्य-निष्पादन में सुधार के लिए वांछित लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु साक्ष्य आधारित पंचायत विकास योजना की तैयारी में स्थानीय लक्ष्य और कार्रवाई योग्य बिंदु निर्धारित करने में मदद करेगा।

*****